Subject: **Fwd: दुरसंचार नियामक आयोग ओपन हाउस डिस्कशन टैरिफ प्लान हेतु सुझाव**
मालवा केबल आपरेटर संघ समिति इन्दौर मध्य प्रदेश की और से
To: Manoj Verma <manoj@trai.gov.in>
Cc: Shreya Jain <shreya@trai.gov.in>

Date: 04/08/16 03:11 PM
From: Group Captain Umesh Kumar <umesh@trai.gov.in>

-------- Original Message --------
From: **malwacableoperatorsangh** <malwacableoperatorsangh@gmail.com>
Date: Apr 8, 2016 2:02:53 PM
Subject: Fwd: दुरसंचार नियामक आयोग ओपन हाउस डिस्कशन टैरिफ प्लान हेतु सुझाव मालवा केबल आपरेटर संघ समिति इन्दौर मध्य प्रदेश की और से
To: pradvbcs@trai.gov.in
Cc: umesh@trai.gov.in

Sent from Samsung Mobile

-------- Original message --------
From: rahul rawat <srk66077@gmail.com>
Date:08/04/2016 13:56 (GMT+05:30)
To: Malwacableoperator Sangh <malwacableoperatorsangh@gmail.com>
Cc:
Subject: दुरसंचार नियामक आयोग ओपन हाउस डिस्कशन टैरिफ प्लान हेतु सुझाव मालवा केबल आपरेटर संघ समिति इन्दौर मध्य प्रदेश की और से

श्रीमान
दुरसंचार नियामक आयोग इडिया
महानगर दुरसंचार भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड)
जाकिर हुसैन कालेज के पास
नई दिल्ली -110002
महोदय
सर्वप्रथम आप को बहुत शुभ कामनाएं व धन्यवाद कि आपने देश के केबल आपरेटरों की समस्या के निराकरण हेतु ओपन हाउस डिस्कशन रखा । मालवा केबल आपरेटर संघ समिति इन्दौर मध्य प्रदेश के इस विषय मैं प्रस्तावित मुख्य बिंदु जो इस प्रकार से है जो टैरिफ रेट को तय करने में सहायक सिद्ध होगे वह निम्नलिखित है
1) अगर देश को सही तरीके से डिजिटलाईज करना है तो उपभोक्ताओं को तर्कसंगत सेवा मुल्य आधारित निम्न दरों पर उपलब्ध कराना होगी ।
2) CAS की अवधारणा को ट्राई को स्वीकार करना होगा जिसमें देश के केबल आपरेटरों का बैसिक सर्विस चार्ज जो CAS में तय किया गया था वह 100 प्रति कनेक्शन के हिसाब से देना होगा ताकि वह व्यवयास को सुचारू रूप से चला सके ।
3) पै चैनल ब्राडकास्टर एड फ्री चैनल हाई डेफिनेशन के माध्यम से पेश करे जिसके लिए न्यूनतम से अधिकतम दरो पर प्रति चैनलों पर रेट तय किया जाए क्योंकि देश की आबादी का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है व उन की आय का स्रोत अनियमित है वे आवश्यकता के अनुसार टीवी चैनलों को सब्सक्राइब कर सके व शिक्षा व ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो ।
4) दो तरीको से सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध किया जाए
1) स्टेंडर्ड सेट टॉप बॉक्स व हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स जिसमें फ्री टू एयर चैनल व पै चैनल की सुविधा विज्ञापनों के साथ जिसमें दरें न्युनतम स्तर पर हो ताकि ब्राडकास्टर व केबल आपरेटर व्यवयास मैं संतुलन बना सके ।
2) हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स के साथ फ्री टू एयर चैनल व विज्ञापन रहित केबल टीवी जिसमें दरें न्युनतम से उच्चतमस्तर की हो ।

वर्तमान में ब्राडकास्टर स्टेंडर्ड बाक्स पर प्रसारित चैनलों का रेट व हाई डेफिनेशन चैनलों के रेट अलग से ले रहे है व एक ही चैनल का भुगतान दो बार करना पड रहा है व MSO और BROADCASTER की मौज हो रही है ।
5) सेट टॉप बॉक्स की कीमत ट्राई के द्वारा निर्धारित की जाए MSO बिना किसी मुनाफे के अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को ध्यान में रखकर

मुहैया कराई जा सके ।

6) सरकार का अपना इन्क्रीपशन सिस्टम हो जिससे नियामक यह मानिटर कर सके की देश में कितने प्रतिशत लोग इस सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं वास्तविक आकडे सरकार के पास उपलब्ध होगे ।

7) सरकारी केस सिस्टम होने पर सेट टॉप बॉक्स इन्टरपोर्टेबलिटी संभव हो सकती हैं व उपभोक्ताओं को अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर केबल टीवी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है ।

8) समपुर्ण भारत में सुचारू रूप से

डिजिटलाईजेशन करने के लिए केबल टीवी सेवा व सेट टॉप बॉक्स पर आरोपित समस्त करो (VAT ST IMPORT DUTY) से 10 वर्षो के लिए मुक्त करवाने की कार्रवाई की जाए ।

9) OTT व VAS आधारित सेवाओं को उपभोक्ताओं को प्रदान करने पर केबल आपरेटरों की हिस्सेदारी तय की जाए ।

10) सरकार द्वारा प्रदत्त पेन इंडिया लायसेंस प्राप्त MSOs कम्पनियों को केबल आपरेटर के शुल्कों का निर्धारण उसके आय व्यय के हिसाब से तय किया जाये क्योंकि उक्त लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों का स्थापना का खर्चा एक बार का हैं व आमदनी के स्त्रोत पेन इंडिया जुड़ें हुए केबल आपरेटर हैं वही केबल आपरेटरों को नेटवर्क रखरखाव व सर्विस पर सबसे अधिक खर्च होता है अतः टैरिफ का निर्धारण इस प्रकार से हो की दोनों के आर्थिक हितों मैं टकराव उतपन्न न हो

11) ब्रॉडकास्टर चैनलों के टैरिफ निर्धारण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर नियामक आयोग को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वह दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है एक तरफ RIO की माँग करता है व बाद में उस का विरोध करता है क्योंकि उसकी TRP मैं गिरावट आ रही है वही दुसरी तरफ चैनलों की बंडल बिलिंग का समर्थन इस तर्क के साथ कर रहा है की देश में अभी पुर्ण डिजिटलाईजेशन नहीं हुआ है व उसकी आय का स्तर गिर गया है जबकि विज्ञापन व प्रति कनेक्शन से भरपुर आमदनी प्राप्त कर रहा है ।

12) डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए केबल आपरेटर सरकार के साथ हैं व उसका स्वागत करता है पर अपने व्यवसाय को दाँव पर लगा कर नहीं ।

डिजिटलाइजेशन में आज सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है वह है बैंडविड्थ का उपलब्ध नहीं हो पाना डिजिटलाईजेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बैंडविड्थ पर उच्च स्तर पर दरें होने के कारण व टेलिकॉम कंपनियों द्वारा सही सर्विस नहीं देने के कारण डिजिटलाईजेशन अवरुद्ध हो रहा है अत : देश की दो बड़ी सरकारी संस्थाएं जो नियामक आयोग के अधीन है MTNL & BSNL उनसे सस्ती दरों पर बैंडविड्थ देश के हर केबल आपरेटर को उपलब्ध करवाई जाए ताकि डिजिटल इंडिया की अवधारणा को पुर्ण रूप से साकार किया जा सके ।

मालवा केबल आपरेटर संघ समिति इन्दौर मध्य प्रदेश की और से पुनः शुभकामनाएँ

जय हिंद जय भारत

राहुल रावत (सचिव)

मालवा केबल आपरेटर संघ समिति इन्दौर मध्य प्रदेश

149 / स्वामी द्वयानंद नगर माणिकबाग रोड इंदौर मध्यप्रदेश 452014

malwacableoperatorsangh@gmail.com

08/04/2016

--

Group Captain Umesh Kumar **ग्रुप कप्तान उमेश कुमार**
Joint Advisor **संयुक्त सलाहकार**
Broadcast and Cable Services Division **प्रसारण और केबल सेवाएं प्रभाग**
Telecom Regulatory Authority of India **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**
Mahanagar Doorsanchar Bhawan **महानगर दूरसंचार भवन**
J.L.Nehru Marg, Old Minto Road **जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पुराना मिंटो रोड**
(Near Zakir Hussain College) **(ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के समीप)**
New Delhi - 110002 **नई दिल्ली - 110002**

Ph. No: +91 11 232664252 (Off); Telefax: +91 11 23220442; Mob: +91 964-380-4851

Email: umesh@trai.gov.in

Your Attitude, not your Aptitude, will determine your Altitude - Zig Ziglar